'लम्बी फेहरिस्त होती जा रही है, उन लोगों की जो, मोदी को और भाजपा को राइट ऑफ करना चाहते हैं'

पर, क्या वाकई मोदी व भाजपा इतने संकट में हैं, राजनीतिक दृष्टि से?

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 मई। क्या मोदी सरकार की संभावनाएं 2024 के चुनावों में औंधे मुंह गिर रही हैं?

पहले तीन चरणों के मतदान से संकेत मिलता है कि प्रधानमंत्री मोदी परेशानी में हैं। वे लगातार विभाजनकारी मुद्दे उठा रहे हैं और वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। क्योंकि जो सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के पास इन सवालों के जवाब नहीं है।

प्रधानमंत्री लगातार हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा रहे हैं, जो वे हर चुनाव में करते हैं पर इस बार आम जनता में इस मुद्दे के प्रति कोई उत्साह नहीं है।

मोदी अपने नारे "अबकी बार 400 पार" के जाल में फंस गए हैं। यह नारा मोदी और शाह की देन है और अब यह उन्हीं के गले की घंटी बन गया है।

- शौकिया मनोवैज्ञानिकों ने कारण ढूँढ़ लिये हैं कि, मोदी बार-बार क्यों हिन्दू-मुस्लिम दुराव की बात कर रहे हैं।
- पर, एक बात यह भी है कि, क्या मोदी केवल पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा रखने के लिए अगली सरकार बनाने का दंभ भर रहे हैं या कोई ठोस स्कीम या प्लान है, जो शुरु के नतीजे भाजपा के माफिक हों।
- आर.एस.एस. व भाजपा के बीच मतभेद की बात भी क्या केवल मियाँ-बीवी के बीच रूठने मनाने का क्रम है और अंततोगत्वा वे एक हैं और एक ही रहेंगे हिन्दुत्व की रक्षा में।

कांग्रेस ने संविधान बदलने के उनके इरादों के खिलाफ इतना भारी प्रचार किया कि वह जनता के दिलो दिमाग में बैठ गया।

दूसरा मुद्दा है दलितों, ओ.बी.सी. व अन्य का आरक्षण। विपक्ष का कहना है कि भाजपा की योजना आरक्षण खत्म करने की है। ये सबसे बड़े मुद्दे बन गए हैं। हालांकि भाजपा इन मुद्दों, जो उसे चुनाव में नुकसान पहुंचाने वाले हैं, से ध्यान हटाने की पूरी कोशिश कर रही है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि आर.एस.एस. के कार्यकर्ता घर बैठे हैं, यह बात भाजपा के लिए काफी खतरनाक है क्योंकि आर.एस.एस. कार्यकर्ता भाजपा की ताकत है। भाजपा कार्यकर्ता भी चुप बैठे हैं और वोटों को सक्रिय करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मोदी सुपर पावर की तरह काम करते हैं और अगर जरुरत ना हो तो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हैं।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज का गरीब तबका किसान, मजदूर आदि चुप बैठे हैं और यह नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने किसको वोट दिया है,

अल्पसंख्यक भी इस बार विभाजित नहीं है और वे उस प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं जो भाजपा को हरा सकता है।

परिवर्तन दिख रहा है और जमीनी स्तर से मिल रही रिपोर्ट्स से ऐसा लगता है कि, नरेन्द्र मोदी मुश्किल में नहीं बल्कि बड़ी मुश्किल में हैं।

मु.मंत्री भजनलाल ने वारंगल में जनसभा की

वारंगल, 9 मई (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को तेलंगाना के वारंगल में भाजपा प्रत्याशी अरूरी रमेश के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि, कांग्रेस ने देश को लूटने एवं बांटने का काम किया है। कांग्रेस ने तुष्टिकरण की सारी सीमाएं पार कर दी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, कांग्रेस द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्व. नरसिम्हा राव के किए गए अपमान को वारंगल की जनता भूली नहीं है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने स्व. नरसिम्हा राव को भारत रत्न से विभूषित किया है। उन्होंने कहा कि, तेलंगाना की जनता कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। यहां कारोबारियों और उद्यमियों को परेशान किया जा रहा है और भ्रष्टाचार का डबल आर टैक्स लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि, इस लोकसभा चुनाव में एक तरफ देश को लूटने वाले हैं तो दूसरी तरफ मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की पांचवी सबसे बडी अर्थव्यवस्था बन चुका है और दुनिया की तीसरी बडी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इस दौरान उन्होंने आव्हान करते हुए कहा कि, सभी लोग अपने वोट की ताकत पहचानें और भाजपा प्रत्याशी अरूरी रमेश को भारी मतों से विजयी बनाएं।

ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में आर.यू.एच.एस. के वी.सी. डॉ. सुधीर भंडारी ने इस्तीफा दिया

डॉ. धनंजय अग्रवाल आर.यू.एच.एस. के कार्यवाहक कुलपति नियुक्त

जयपुर, 9 मई। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एन.ओ.सी. मामले में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुधीर भंडारी ने गुरूवार को बर्खास्तगी के डर से राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। कुछ देर बाद ही राज्यपाल ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। कहा जा रहा है कि, राज्य सरकार ने भी इस मामले में डॉ. भंडारी को बर्खास्त करने की पूरी तैयारी कर ली थी और इसके लिए दोपहर बाद चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें जांच रिपोर्ट सौंपकर डॉ. भंडारी की भूमिका की जानकारी दी।

- चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी तथा राज्य सरकार ने भंडारी को बर्खास्त करने की सिफारिश की।
- चिकित्सा मंत्री ने कहा कि, इस मामले की पेपर लीक प्रकरण की तर्ज पर ही जाँच होगी।

राज्यपाल कलराज मिश्र ने रात को आदेश जारी कर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलोजी विभाग के वरिष्ठ आचार्य डॉ. धनंजय अग्रवाल को आर.यू.एच.एस. का कार्यवाहक कुलपति नियुक्त किया है।

गौरतलब है कि, इस मामले में पहले ही राज्य सरकार एस.एम.एस. के अधीक्षक डॉ. अचल शर्मा और एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजीव बगरहट्टा को पद से हटा चुकी है। डॉ. सुधीर भंडारी को भी पहले इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इस मामले में उनकी कोई भूमिका होने से इन्कार करते हुए इस्तीफा देने से मना कर दिया था। इसके बाद चिकित्सा मंत्री खींवसर ने डॉ. भंडारी को पद से हटाने के लिए राज्यपाल से मिलकर सिफारिश करने की घोषणा की थी।

राज्य में पिछले दो दिनों से चल रहे घटनाक्रम में पहले एस.एम.एस. अधीक्षक और प्राचार्य को हटाया गया और उसके बाद कुलपति को बर्खास्त करवाने की बात कही गई। इसके बाद चिकित्सा मंत्री दिल्ली चले गए और एक दिन पहले राज्यपाल भी दिल्ली गए थे। ऐसे में, बीच का रास्ता तलाशने के लिए कुलपति डॉ. सुधीर भंडारी भी बुधवार को दिल्ली ही थे, लेकिन उनकी बात नहीं बन पाई। देर रात चिकित्सा मंत्री ने जयपुर लौटते ही दोपहर को राज्यपाल से मिलने की बात कही। सुबह चिकित्सा मंत्री के राज्यपाल के पास जाने की खबर वायरल होते ही करीब 11 बजे डॉ. सुधीर भंडारी राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंच गए। उन्हें मनाने की कोशिश की लेकिन राज्यपाल ने चिकित्सा मंत्री का पक्ष जाने बिना कोई निर्णय करने मना कर दिया। इस पर डॉ. भंडारी राज्यपाल को अपना इस्तीफा देकर लौट गए तथा दोपहर बाद चिकित्सा मंत्री ने विभाग के अधिकारियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात कर पूरी जांच रिपोर्ट सौंपी और बताया कि, इस मामले में डॉ. भंडारी की कितनी भूमिका रही है। इसके बाद राज्यपाल ने डॉ. भंडारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया।

राज्यपाल से मिलने के बाद चिकित्सा मंत्री खींवसर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, पिछली सरकार में डॉ भंडारी का सारा कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड था। डॉ. भंडारी को एक के बाद एक प्रमोशन दिए गए। उन्होंने कहा कि, जैसे पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की है, उसी तरह इस मामले में भी आरोपियों के जहां भी तार जुड़े हैं, उन तक पहुंचा जाएगा। उन्हें बेनकाब कर सजा दिलवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि, फर्जी एन.ओ.सी. के जरिये ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने का मामला साल 2020 से चल रहा है। उन्होंने निजी अस्पतालों पर भी कड़ी कार्रवाई की बात कही।

गौरतलब है कि, ए.सी.बी. ने गत दिनों रिश्वत लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एन.ओ.सी. देने के मामले में एस.एम.एस. हॉस्पिटल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह को गिरफ्तार किया था।

इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल फोर्टिस और ई.एच.सी.सी. के एक-एक अधिकारी को पकड़ा था। इसके कुछ दिनों बाद ही हरियाणा के गुरूग्राम में पैसे लेकर मानव अंग ट्रांसप्लांट करवाने का मामला सामने आया था। इस मामले में कई ट्रांसप्लांट जयपुर में ही हुए थे।

'हमारी सरकार में मुझ पर देशद्रोह ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पायलट ने कहा, पुरानी हिस्ट्री देख लीजिए, जब हम सत्ता में थे तो एक बार 56 सीटें आईं, फिर 21 सीटें आईं। इस बार राजस्थान में हमारे 71 विधायक हैं। यह अलग बात है कि हम सरकार रिपीट नहीं कर पाए। हम सामूहिक रूप से एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। कोई कड़वाहट नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ मुद्दों पर अलग राय हो सकती है। हमारा मकसद सरकार बनाना था। हम मिलकर चुनाव लड़े थे। पहले जहां सत्ता में रहते हुए 21 सीटें आती थीं, इस बार हमारे 71 विधायक हैं।

सियासी संकट के वक्त गहलोत सरकार पर फोन टैप करने के, गहलोत के पूर्व ओ.एस.डी. लोकेश शर्मा के बयान के बारे में पूछने पर पायलट ने कहा कि, नेतृत्व परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन दो अलग-अलग बातें हैं। उस समय हमारे कुछ मुद्दे थे। हम चाह रहे थे कि, उन मुद्दों में सरकार को कोर्स करैक्शन करने की जरूरत है। सरकार में कुछ बदलने की बातें थीं। पार्टी के सामने हमने बातों को रखा, बात सुनी गई और फिर सरकार और पार्टी स्तर पर बदलाव हुए। हम जो काम करेंगे वो ही रिज़ल्ट मिलेगा।

कांग्रेस नेताओं ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का यदि यह आरोप सत्य है तो वो भ्रष्टाचार की जांच के लिए ई.डी. व आयकर विभाग को जांच के लिए क्यों नहीं आदेश देते। पूर्व केन्द्रीय मंत्री शकील अहमद ने भी इस मुद्दे पर कहा कि तीन चरणों का मतदान समाप्त होने के बाद मोदी को अपनी पराजय का डर सता रहा है इसलिए अब उन्होंने अपने ही मित्रों के खिलाफ बोलना प्रारंभ कर दिया है।

महिला कांग्रेस अध्यक्ष अल्का लांबा ने भी कहा कि अब देखना यह है कि क्या ई.डी. और आयकर विभाग प्रधानमंत्री से उनके द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बारे में पूछताछ करेगी जो उन्होंने उनके दो ज़िगरी मित्रों पर लगाए हैं। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने चुनौती देते हुए कहा कि ई.डी. एवं आयकर विभाग प्रधानमंत्री के अधीन है अत: उनकों अपने मित्रों पर छापे मारने का आदेश देना चाहिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अडाणी व अंबानी के खिलाफ जांच करने के लिए ई.डी. एवं सी.बी.आई. को भेज देना चाहिए।

प्र.मंत्री मोदी और राहुल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनौती पेश करते हुए कहा गया है कि "18वीं लोकसभा के लिए चल रही वोटिंग प्रक्रिया अपना आधा रास्ता तय कर चुकी है। सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता रैलियों और सार्वजनिक संबोधनों में हमारे संवैधानिक लोकतंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल उठा चुके हैं।"

उक्त तीनों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में रेखांकित किया गया है कि प्रधानमंत्री ने आरक्षण, धारा 370 और धन-सम्पत्ति के पुर्नवितरण पर कांग्रेस को खुले आम चुनौती दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान की संभावित काट-छांट, इलैक्टोरल बॉण्ड स्कीम और चीन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक सार्वजनिक बहस करने की भी चुनौती दी है।

पत्र में एक प्रस्ताव के साथ ही रिप्लाई एड्रैस भी दिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, बहस का स्थल, अवधि और फॉर्मेट की शर्तें वे ही होंगी जिन पर प्रधानमंत्री और राहुल गांधी दोनों सहमत हो जाए और ये नेता यदि स्वयं बहस नहीं करना चाहते तो वह इसके लिए अपने-अपने प्रतिनिधि मनोनीत कर सकते हैं।

मदन बी. लोकुर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, जबकि ए.पी. शाह दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस हैं। एन. राम एक सीनियर पत्रकार और "द हिंदू" अखबार के पूर्व संपादकीय प्रभारी हैं।

भारी मतदान के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिससे साबित होता था कि शिकायत दुर्भावनापूर्ण थी।

राज्यपाल बोस ने राजभवन में पुलिस को प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी थी और स्थानीय पुलिस का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बंद कर दिया था।

राज्यपाल बोस ने कुछ विशेष नागरिकों को सी.सी.टी.वी. पर फुटेज कवरेज देखने के लिए आमंत्रित किया है और उन्होंने कहा था कि वे प्रैस के लोगों से स्वयं बात करेंगे। हालांकि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों और मंत्रियों का राजभवन में प्रवेश निषेध कर दिया था। बंगाल के चुनावी माहौल में आरोप घने व तेजगति से मंडरा रहे हैं। जनता बुद्धिमान नज़र आ रही है पर वे थोड़े संकेत देने लगे है कि वो किसे वोट देने वाले हैं।

'देश की जनसंख्या में 1950...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सभी नीतिगत कार्यवाहियों, राजनीतिक निर्णयों और सामाजिक प्रक्रियाओं का शुद्ध परिणाम समाज में बढ़ती विविधता के लिए एक सकारात्मक वातावरण उपलब्ध करवाना है।

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि बहुसंख्यक समुदाय की घटती आबादी के वैश्विक रूझान के क्रम में भारत में भी बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय की आबादी के शेयर में 7.82 प्रतिशत कमी देखने को मिली।

पेपर में कहा गया कि दक्षिण एशियाई पड़ौसी देशों के वृहद संदर्भ को देखते हुए यह अपने आप में खास है क्योंकि उन पड़ौसी देशों जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और अफगानिस्तान में बहुसंख्यक लोगों की आबादी बढ़ी है, जबकि अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की आबादी में भारी गिरावट आई है।

पेपर में कहा गया कि यह तथ्य आश्चर्यजनक नहीं है, तभी तो उत्पीड़न के समय के दौरान पड़ोस के देशों की अल्पसंख्यक आबादी भारत आकर बसी। रिपोर्ट ने संकेत दिया कि, सभी मुस्लिम बहुल देशों में, बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय के शेयर में वृद्धि देखी गयी सिवाय मालदीव के, जहां बहुसंख्यक गुट (शफी सुन्नी) में 1.47 प्रतिशत की कमी आयी।

बांग्लादेश में, बहुसंख्यक धार्मिक समूह के शेयर में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जो कि, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में, बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय (हनाफी मुस्लिम) के शेयर में 3.75 प्रतिशत वृद्धि और कुल मुसलमानों की जनसंख्या में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि सन् 1971 में बांग्लादेश बन चुका था।

रिपोर्ट के अनुसार, गैर-मुस्लिम बहुल देशों, भारत, म्यांमार और नेपाल में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदायों में कमी देखी गई।

रिपोर्ट में वर्ष 1950 को बेसलाइन वर्ष लेने के दो प्रमुख कारण हैं।

रिपोर्ट ने कहा, यही समय था जब संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकारों की रूपरेखा बनी थी, अल्पसंख्यक के अधिकारों और अल्पसंख्यकों के संरक्षण के प्रति राज्य की जिम्मेवारी को अंतरराष्ट्रीय कानून की मुख्य धारा में लाया गया था।

यह रिपोर्ट दुनिया भर में सन् 1950 से सन् 2015 के बीच के 65 वर्षों में अल्पसंख्यकों की उस देश की जनसंख्या में बदलते शेयर की स्थिति पर एक विस्तृत वर्णनात्मक विश्लेषण है। जिन 167 देशों में यह विश्लेषण किया गया वहां, बेसलाइन वर्ष 1950 में, बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय के शेयर की औसत वैल्यु 75 प्रतिशत थी, जबकि, वर्ष 1950 से वर्ष 2015 के बीच बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय के बदलाव का औसत 21.9 है। सरसरी तौर पर देखने से पता चलता है कि वर्ष 1950 से वर्ष 2015 के बीच की जानकारी उठाने और जारी करने का फैसला बड़ी ही अक्लमंदी से किया गया है ताकि ऐसा नेरेटिव बनाया जा सके तो सत्तारूढ़ पार्टी के अनुकूल हो।

प्र.मंत्री मोदी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है, जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जो कि वर्ष 2019 के चुनावों से केवल एक कम है। इस बार, नीतीश कुमार का प्रभाव और राजनीतिक प्रतिष्ठा, कथित तौर से, उनके बार-बार पाला बदलने और उनकी आयु के कारण कम हो गयी है। दूसरी तरफ शिव सेना का एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार की एन.सी.पी. एक अलग पार्टी के रुप में, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं।

"इशु लैस" चुनाव ने सभी को डरा रखा है, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सीमित व कम होती है, इसीलिए चार महीने पहले जनमानस में गहलोत सरकार के सर्वव्यापी भ्रष्टाचार के कारण जो रोष था, उद्वेग था, वह कुछ धुंधला पड़ गया, नहीं तो वह जनआक्रोश अपने आप पर्याप्त था, आम आदमी के मन में चुनाव के प्रति उदासीनता के बादलों को भेदने के लिये। पर, यह भी सच है कि, दूसरी ओर भाजपा भी इतनी प्रचंड लहर नहीं पैदा कर सकी, प्र.मंत्री मोदी के पक्ष में कि, जनता उमड़-उमड़ कर झुण्डों में आती वोट देने।

इस "इशू लैस" चुनाव में क्या "रिज़ल्ट" रहेगा, इसका भय भाजपा, कांग्रेस, अफसर, पुलिस तथा सत्ता के गलियारों में चक्कर लगाने वाले आधे-अधूरे से दलालों, सबको सता रहा है। इन लोगों को भय है कि, अगर अपनी दुकानों में गलत सामान रख लिया तो बिक्री तो छोड़ो, लेने के देने पड़ जायेंगे। इन समुदायों के नेताओं, कई जातियों को भय है कि, अब तक प्रचलित कई राजनीतिक किंवदंतियां व धारणाएं, नेस्तनाबूद हो सकती हैं, चुनाव के नतीजों से। विधानसभा चुनावों में धारणा फैली थी कि, शेखावाटी में (सीकर, झुंझुनूं, चूरू) जाटों ने हर बार की तरह अपना वोट बंटने नहीं दिया और कांग्रेस के पक्ष में जमकर मतदान किया, जिससे शेखावाटी में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। पर, इसी क्षेत्र के एक वरिष्ठतम जाट नेता का इससे भिन्न सोच है। उनका कहना है, जाट वोट विभाजित हुआ, 60:40 या 55:45 के अनुपात में। पर, कांग्रेस विजयी हुई मुसलमान व एस.सी. मतदाताओं के एकतरफा कांग्रेस के समर्थन के कारण। अगर यह प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के रिज़ल्ट में दोहराया जाता है तो, प्रदेश की राजनीति में भारी बदलाव लायेगा। स्वाभाविक ही है, जाट समुदाय इस संभावना से व्यथित है, डरा हुआ सा है।

एक और धारणा प्रचलित है कि, मूल ओ.बी.सी. (माली, धोबी, प्रजापत, कुम्हार, सुनार आदि) सदा से भाजपा का अभेद्य किला रहे हैं। तथा अब तक इस मूल ओ.बी.सी. वर्ग ने भाजपा को, जाटों, एस.सी. व अल्पसंख्यक वर्ग के "ऑन स्लॉट" (भारी मतदान) के परिणामों से बचाया है। इस धारणा का भी टैस्ट होगा कि, यह धारणा प्रमाणित होगी या अप्रमाणित साबित होगी लोकसभा चुनाव के नतीजों से।

यह भी माना जाता है कि, महिलाएं जम कर वोट करेंगी भाजपा के लिये, मोदी जी के लिये, क्योंकि राम मंदिर बनना उनके लिये भावना व श्रद्धा का विषय है, अत: भारी संख्या में वोट देकर, वे अपने आपको उऋण महसूस करना चाहेंगी। इस बार चुनाव के पूर्व यह बात भी खूब फैली थी कि, भाजपा के प्रति राजपूत कुछ अनमने से हैं, रूपाला प्रकरण से, राजेन्द्र राठौड़ की तथाकथित अवहेलना से, आदि, आदि। अगर यह अनमनापन राजनीतिक दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से बेअसर रहा तो वाकई में चिन्ता का विषय रहेगा और भय व आशंका का कारण बनेगा, आत्मसम्मान से ओत-प्रोत समाज के लिये।

पिछले विधानसभा चुनावों में गुर्जर कांग्रेस से विमुख हो गये थे तथा भाजपा की ओर बढ़ गये थे, पार्टी में अपने लाड़ले नेता सचिन पायलट को लगातार तिरस्कृत व अपमानित होता देखकर। इस तिरस्कार का मूल वे गहलोत को मानते थे तथा हाईकमान किन्ही कारणों से मूकदर्शक बनकर रह गया था इस पूरे प्रकरण में। इस बार इस समुदाय ने यह महसूस किया कि, पायलट की चली है लोकसभा चुनाव में। उदाहरण के लिये, उनके कहने से, उनके नौ-दस समर्थकों को टिकट मिले। अत: लोकसभा चुनाव में किसी हद तक गुर्जरों की कांग्रेस में वापसी हुई है। पायलट ने भी अवसर का पूरा लाभ उठाया तथा अपने समर्थकों के क्षेत्र में आम सभाएं, रोड शो किये। जबकि गहलोत, धृतराष्ट्र की भांति पुत्र मोह से ग्रसित, अधिकतर वैभव के चुनाव तक ही सीमित रहे। रिज़ल्ट से पायलट व उनके समर्थक भयभीत नहीं हैं, क्योंकि जिन सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावना देखी जा रही है और जहां जीत पक्की सी मानी जा रही है (दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर ग्रामीण) सभी पायलट के क्षेत्र माने जाते हैं। अगर जीत न भी हो तो भी यह तो अवश्य ही कहा जा सकता है कि, भाजपा की जीत का मार्जिन बहुत कम होगा, अन्य सीटों की तुलना में।

गहलोत की चिंता व भय का एक बड़ा कारण यह भी है कि, अगर भाजपा का स्कोर 25.0 रहा तो गहलोत समर्थक राजनीतिक नेता व अफसर भाजपा के समक्ष अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए, अपना-अपना मुंह खोलने लगेंगे, गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार व कुप्रबंधन के सबूत पेश करने के लिये। गहलोत के प्रबल समर्थक, जिनको अपनी सरकार बचाने के लिये टिकट दिलाने में गहलोत पूरी तरह अंतिम क्षणों तक प्रयासरत थे, व दर्जनों अन्य नेता अब पार्टी बदलकर, भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। फोन टैपिंग, पेपर लीक और किडनी ट्रांसप्लांट, ऐसे सदाबहार प्रकरण हैं, जिन पर गहलोत सरकार को कभी भी लपेटा जा सकता है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908